



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2016/भाद्र 25, 1938

No. 652]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2016/BHADRA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2016

सं. 44/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 890(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 06.09.2004 जिसे सा.का.नि. 572(अ) दिनांक 06.09.2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, फार्म ए.आर.ई. 2 में-

(i) शीर्ष 'घोषणा' में, मद (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के स्थान पर निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(घ) हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि खेप के निर्यात पर इस आवेदन के अंतर्गत:-

(i) हम कॉलम शीर्ष 'प्रति अदायगी जब सेनवेट की सुविधा नहीं ली गई हो' जो कि कुल प्रति अदायगी (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर घटक को एक साथ मिलाते हुए) को संदर्भित करता है, में विनिर्दिष्ट दरों और ऊपरी सीमा पर किसी प्रति अदायगी का दावा नहीं करेंगे।*

या

- (ii) हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 के अंतर्गत डीजल पर लगाए गए रियायती शुल्क या नियम 19 के उपनियम (2) के अंतर्गत खरीदे गए डीजल पर किसी भी प्रति अदायगी के लिए दावा नहीं करेंगे।*

*जो लागू न हो उसे काट दें।;

(ii) भाग क में, शीर्ष 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण' के अंतर्गत क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

"3. हमने रिकार्ड से तथा पृष्ठ के पीछे क्रम सं. 3 पर सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट को न लिए जाने के बारे में और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम (2) के अंतर्गत डीजल की खरीद किए जाने और न किए जाने के बारे में, जहां भी लागू हो, विनिर्माता के द्वारा की गई घोषणा का सत्यापन कर लिया है और उसे सही पाया है।";

(ii) भाग ख में, शीर्ष 'सीमाशुल्क अधिकारियों के द्वारा प्रमाणीकरण' के अंतर्गत, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2. (क) प्रमाणित किया जाता है कि निर्यात को निम्नलिखित कॉलम शीर्ष 'प्रति अदायगी, जब सेनवेट सुविधा न ली गई हो', जो कि सीमाशुल्क घटक को संदर्भित करता है, में विनिर्दिष्ट दर और ऊपरी सीमा से संबंधित शुल्क प्रति अदायगी योजना के अंतर्गत किया गया है।"

या

प्रमाणित किया जाता है कि निर्यात को शुल्क प्रति अदायगी योजना के अंतर्गत नहीं किया गया है। *

(* जो लागू न किया गया हो उसे काट दें।)

(ख) आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऐसे निर्यात को मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस या गुणवत्ता आधारित अग्रिम लाइसेंस, जो कि 31.03.1995 के पहले जारी किए गए हो, के अंतर्गत निर्यात दायित्वों के निर्वहन में नहीं किया गया है।"

[फा. सं. 268/01/2016-सीएक्स 8]

रोहन, अवर सचिव

[प्रधान अधिसूचना सं. 21/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 06 सितंबर, 2004 को सा.का.नि. 572(अ) दिनांक 06 सितंबर, 2004 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 01 मार्च 2016, जिसे सा.का.नि. 252(अ) दिनांक 01 मार्च 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।]

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2016

No. 44/2016- Central Excise (N.T.)

G.S.R. 890(E).—In exercise of the powers conferred by rule 18 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Government being satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2004-CE (N.T.) dated 06.09.2004, published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide GSR 572(E), dated the 6th September, 2014, namely:-

In the said notification, in Form A.R.E. 2,-

- (i) under the heading Declaration, for item(d) and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto, shall be substituted, namely;-

“(d) We further declare that on export of the consignment under this application:-

- (i) we shall not claim drawback on rates and caps specified below the column heading ‘Drawback when Cenvat facility has not been availed’ which refers to the total drawback (Customs, Central Excise and Service tax component put together)*

or

- (ii) we shall not claim any drawback as rebate of duty on diesel which has been claimed by us under rule 18 or diesel which has been procured by us under sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002.*

*strike- off whichever is not applicable” ;

(ii) in PART A, under the heading CERTIFICATION BY THE CENTRAL EXCISE OFFICER, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely;-

“3. I have verified with the records, the declaration of the manufacturer given at Sl. No. 3 overleaf regarding non-availment of credit under CENVAT Credit Rules, 2004 and procurement and non-procurement of diesel under rule 18 or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 as applicable, and found the same to be true.”;

(ii) in PART B, under the heading Certification by the Officer Of Customs, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely;-

- “2. (a) Certified that the exports, are under Duty Drawback Scheme on rates and caps specified below the column heading ‘Drawback when Cenvat facility has been availed’ which represents Customs component.*

or

Certified that the exports are not under Duty drawback Scheme.*

(*stike- off whichever is not applicable)

- (b) It is further certified that exports are not in discharge of export obligation under Value Based Advance License or a Quantity Based Advance License issued before 31.03.95.”.

[F. No. 268/01/2016-CX.8]

ROHAN, Under Secy.